सूती धागों की मांग

480. **श्री रामसिंह राठवा:** (क) क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार हथकरघा बुनकरों को उनकी जरूरत के अनुरूप सूती धागा देने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूती धागों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त सूत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी प्रकार की कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:— (1) हैंक यार्न दायित्व आदेश जिसमें प्रत्येक सूत उत्पादक को अपने विक्रेय सूत का कम से कम 50% हैंक के रूप में पैक करना होता है, (2) नई बुनकर सहकारी कताई मिल की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण के लिए ऋण सहायता और (3) हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की योजना। महत्वपूर्ण हथकरघा राज्यों में राज्य स्तर की सूत मूल्य निर्धारण समितियां कार्य कर रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि सूत वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाएं जो मुख्यरूप से राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा वितरित किया जाता है।

जनता-वस्त्र का आवंटन

481. **श्री ईश दत्त यादव:** (क) क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश को 1990-91 के वर्ष में आवंटित जनता कपड़े की तुलना में राज्य को 1991-92 के वर्ष में कम मात्रा में जनता कपड़ा आवंटित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े के आवंटन का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 1990-91 के 132 मिलियन वर्ग मीटर के लक्ष्य से घटा कर 1991-92 में 100 मिलियन वर्ग मीटर किया गया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि देश में जनता कपड़े के 600 मिलियन वर्ग मीटर के लक्ष्य को कम करके 450 मिलियन वर्ग मीटर किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट 165, अनुपत्र संख्या 6]**

देश में बुनकरों की सहकारी समितियां

482. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सहकारी समितियों द्वारा तैयार हथकरघा-वस्तुओं का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों के पास इन समितियों द्वारा तैयार वस्तुओं का कोई भंडार जमा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) विवरण संलग्न है। **[नीचे देखिए]**

(ख) से (घ) सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के उत्पादन और स्टॉक के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) हथकरघा उत्पादों के विपणन में संवर्धन करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित हथकरघा उत्पाद भी शामिल है। इन योजनाओं में विपणन विकास सहायता योजना, राष्ट्रीय डिज़ाइन संग्रह के अंतगर्त उत्पादों के उत्पादन और उनकी प्रदर्शनी, महानगरों में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित करना शामिल है।

विवरण

देश में बुनकर सहकारी समितियां

क्रम सं॰	राज्य का नाम	प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	598
2.	असम	1643
3.	बिहार	1385
4.	गुजरात	1298
5.	हरियाणा	440
6.	हिमाचल प्रदेश	148
7.	जम्मू व कश्मीर	223
8.	कर्नाटक	278
9.	केरल	602
10.	मध्य प्रदेश	504
11.	महाराष्ट्र	842
12.	मणिपुर	1056
13.	उड़ीसा	756
14.	पंजाब	1127
15.	राजस्थान	636
16.	तमिलनाडु	1505
17.	त्रिपुरा	69
18.	उत्तर प्रदेश	4323
19.	पश्चिम बंगाल	1388
20.	मेघालय	28
21.	पांडिचेरी	14
22	मिजोरम	41
23.	दिल्ली	449
24.	नागालैण्ड	74
	कुल:	19,427

Sick NTC mills in Gujarat

483. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of NTC sick textile units in Gujarat due to financial crisis and heavy losses;

(b) whether Government propose to close down these units or implementing worker's cooperative scheme to operate these sick mills;

(c) whether Government have received any proposal form the worker's cooperative to operate these mills to defuse more unemployment; and

(d) whether there is any proposal to introduce golden handshake scheme in NTC units and if so, what is workers/ employees' reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) All the 11 running mills of National Textile Corporation in Gujarat are incurring heavy losses.

(b) to (d) Government have approved a Turn Around Startegy would be selective modernisation, financial and managerial restructuring and rationalisation of surplus workforce through the Voluntary Retirement Scheme. Voluntary Retirement Scheme will also be offered to the officers, staff and workers of such chronically sick mills, which have no possibility of viability and which may have to be closed down or merged with adjacent units to ensure viability. Government is prepared to extend full support to any viable proposal for the cooperativisation of NTC mills provided it bears the consent of all parties concerned. However, no concrete proposal in this regard has been received so far. Voluntary Retirement Scheme is already in vogue in NTC. 248 officers/ staff and 10,380, workers of NTC availed of Voluntary Retirement Scheme upto 31st October, 1992 as part of the Turn around strategy.

Production and export of polyester garments

484. SHRI RAM RATAN RAM : Dr. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) the polyester garments produced in Uttar Pradesh during the last three year;